बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 320457 पटना, दिनांक:- 08/08/17

ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0(बैंक शि0)-102-35/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

संयोजक,
बिहार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
पश्चिम गांधी मैदान, पटना ।

विषय:- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के बैंक खाता में आवास निर्माण हेतु अंतरित सहायता राशि से लाभार्थियों के ऊपर बैंक का बकाया लंबित राशि की कटौती नहीं करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का अ0स0पत्र सं0-J-11060/32/2017-RH दिनांक-03.07.17

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों के बैंक खाता में आवास निर्माण हेतु अंतरित सहायता राशि से लाभार्थियों के ऊपर बैंक का बकाया लंबित राशि की कटौती नहीं करने हेतु सभी बैंकों को आवश्यक निदेश देने का अनुरोध भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से किया गया है क्योंकि आवास निर्माण की सहायता राशि से बैंक द्वारा बकाया लंबित राशि की कटौती कर लेने से लाभार्थियों का मकान अपूर्ण रह जायेगा और "2022 तक सभी को आवास" जैसी भारत सरकार का उद्देश्यपरक योजना प्रभावित होगी ।

प्रसंगवश उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मार्गदर्शिका में लाभार्थी द्वारा प्राप्त सहायता राशि से 12 माह में मकान का निर्माण कराने का प्रावधान है तथा बिहार राज्य में सहायता राशि का अंतरण लाभुकों द्वारा निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार निम्न रूप से किया जाता है :-

किस्त	राज्य के सामान्य जिलों के लिए (1,20,000)	राज्य के IAP जिलों के लिए (औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर (भभुआ), सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण) (1,30,000)
प्रथम किस्त (आवास की स्वीकृति के उपरांत आवास का प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के लिए)	₹ 50,000 (पचास हजार रूपये)	₹ 55,000 (पचपन हजार रूपये)
द्वितीय किस्त (आवास का प्लिंथ तक के निर्माण कार्य के बाद छत स्तर तक निर्माण कार्य के लिए)	₹ 40,000 (चालीस हजार रूपये)	₹ 45,000 (पैंतालीस हजार रूपये)

किस्त	राज्य के सामान्य जिलों के लिए (1,20,000)	राज्य के IAP जिलों के लिए (औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, रोहतास, जमुई, नवादा, मुंगेर, कैमूर (भभुआ), सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण) (1,30,000)
तृतीय किस्त (आवास का छत स्तर से आवास निर्माण कार्य का फिनिशिंग (प्लास्टर, पेंट, दरवाजा, खिड़की लगाने तथा फ्लोर फिनिशिंग) कार्य को पूर्ण करने के लिए)	₹ 30,000 (तीस हजार रूपये)	₹ 30,000 (तीस हजार रूपये)

लाभार्थियों को सहायता राशि का अंतरण State Nodal Bank Account जो Bank of India, वीरचन्द पटेल पथ, पटना में "रूरल हाउसिंग फण्ड" नाम से संधारित बचत खाता संख्या-441020110000167, IFSC Code-BKID 0004410 से FTO के द्वारा p-FMS के माध्यम से की जाती है ।

अतः भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रसंगाधीन पत्रों की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने स्तर से भी बिहार राज्य में अवस्थित सभी बैंकों को प्रभावी निदेश जारी करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

8/8/17

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 320457, पटना, दिनांक:- 08/08/17

प्रतिलिपि:- (अनुलग्नक सहित) सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उनसे अनुरोध है कि पत्र में वर्णित वस्तुस्थिति से जिला स्तरीय बैंकर्स समिति एवं प्रखण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति को अवगत कराया जाय तथा उनके स्तर से आवश्यक निदेश निर्गत कराने की कार्रवाई की जाय ।

8/8/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 320457, पटना, दिनांक:- 08/08/17

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित भेजते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

8/8/17

सरकार के सचिव

Prasant Kumar
Joint Secretary
Tel 23389828
email: prasant.kumar@gov.in

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110114
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110114

D.O. No. J-11060/32/2017-RH

July 3, 2017

You are aware that under the rural housing scheme "Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin (PMAY-G)" implemented by the Ministry of Rural Development, assistance for construction of the houses is transferred directly to the bank account of the beneficiaries.

2. In this connection, it is stated that a reference has been received from Shri Rajendra Rathore, Minister for Rural Development and Panchayati Raj, Government of Rajasthan (copy enclosed) wherein it was stated that the banks are deducting the balance of loans taken by the beneficiaries from the assistance provided under the PMAY-G which is adversely affecting the implementation of the programme.

3. In this regard, I wish to inform you that in the direction of fulfilment of Government's Objective "Housing for All" by 2022, one crore houses are to be constructed by 2018-19 under PMAY-G in the first phase. The completion period prescribed for a house is 12 months from the date of sanction. This requires seamless transfer and availability of funds with the beneficiaries enabling them to construct their house within the prescribed time limit. The deductions being carried out by the banks on account of outstanding loan from the assistance transferred for construction of the house would affect the completion of the house and thereby would affect the achievement of the objective of the Government.

4. I shall be grateful if you could look into the matter personally and issue necessary instructions to the Banks that outstanding loans of the account holder may not be deducted from the assistance provided under social welfare schemes to these poor beneficiaries.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-
(Prasant Kumar)

Shri R. Gandhi,
Deputy Governor,
Reserve Bank of India,
Central Office Building 16th Floor,
Shahid Bhagat Singh Road,
Mumbai-400 001.

Copy to: All Principal Secretaries/Secretaries of States/UTs dealing with PMAY-G.

(Prasant Kumar)
Joint Secretary(RH)

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली–110114
Ministry of Rural Development
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhavan, New Delhi-110114

Prasant Kumar
Joint Secretary
Tel: 23389828
Email: prasant.kumar@gov.in

D.O. No. J-11060/32/2017-RH

July 3, 2017

Bank accounts of the beneficiaries of Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin (PMAY-G) have been opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY). The central assistance to the States, under PMAY-G, is transferred to the single State Nodal Account and from there the Government transfers the assistance directly to the beneficiary's account through Fund Transfer Order (FTO).

2. Instances have been brought to the notice of the Ministry by some State Governments regarding the difficulties being faced by them for release of the assistance of PMAY-G through PMJDY bank accounts of the beneficiaries because of the ceiling put on the transactions of PMJDY accounts. This issue has already been taken up vide our earlier reference dated 8th June, 2017 (copy enclosed). The other difficulty pointed by the State Government is that the banks are deducting the balance of pending loans against the beneficiaries from the 1st instalment of assistance provided under the PMAY-G. This is causing adverse effect on the implementation of the programme.

3. As you are aware that in order to fulfill Government's commitment to provide "Housing for All", one crore houses have to be constructed under PMAY-G during 2016-17 to 2018-19. The completion period of a house is 12 months. As the banks are deducting the outstanding loans of the beneficiaries from the 1st instalment of PMAY-G, the beneficiaries are unable to complete the house in the stipulated period causing slow implementation of the programme..

4. I shall be grateful if you could look into the matter personally and issue necessary instructions to the Banks that outstanding loans of the account holder may not be deducted from the assistance provided under social welfare schemes to these poor beneficiaries. It will be appreciated if the instructions relating to conversion of PMJDY Account of PMAY-G beneficiaries into Normal account and also removing the transaction limits in PMJDY accounts are also issued to all concerned.

With regards,

Yours sincerely,

Sd/-
(Prasant Kumar)

Shri Amit Agrawal,
Joint Secretary,
Deptt. of Financial Services,
Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi.

Copy to: All Principal Secretaries/Secretaries of States/UTs dealing with PMAY-G.

(Prasant Kumar)
Joint Secretary(RH)